वर्ष 04 अंक 123
पृष्ठ 16

कोलकाता, शुक्रवार
6 नवंबर 2015

कोलकाता संस्करण
मूल्य ₹ 4.00

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

90 फीसदी विवि के पाठ्यक्रम बेकार : सीएनआर राव 4 वे तब चुप रहे थे : तसलीमा नसरीन 6

www.jagran.com पश्चिम बंगाल • बिहार • झारखंड • उत्तर प्रदेश • दिल्ली • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित

स्मार्ट सिटी में मदद को तैयार माइक्रोसॉफ्ट

मुंबई में एक इवेंट के दौरान कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते माइक्रो साफ्ट के प्रमुख सत्या नाडेला। प्रेट्र

नितिन प्रधान, मुंबई

"सरकार जनोपयगी सेवाओं को क्लाउड पर ले जाने के लिए तैयार है। इस बारे में बात हो रही है। इसमें डेटा सेफ्टी अहम बात रहेगी। उन्होंने सत्या नडेला को भरोसा दिलाया कि भारत में लोग किसी नई टेक्नोलॉजी को थोड़ा इंतजार कर परखते हैं, मगर इसके बाद इस्तेमाल में वे पीछे नहीं रहते।

रविशंकर प्रसाद
संचार और आइटी मंत्री

"गांधी जी ने छोटे स्तर पर चीजों को करने को तवज्जो दी थी। वह टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए सही रोल मॉडल हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह के कदम उठा रही है, उससे नडेला के सामने मौका है कि वह डिजिटल दुनिया के नए गांधी बन सकते हैं।

आनंद महिंद्रा
चेयरमैन महिंद्रा एंड महिंद्रा

नडेला की पहल

- दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी इसके लिए मुहैया कराएगी फंड
- स्टार्ट अप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी मदद का एलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी कार्यक्रम को देखते हुए टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्मार्ट सिटी की दिक्कतों के निदान को ध्यान में रखते हुए भारत में स्थानीय स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। देश में स्मार्ट शहरों की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इन स्टार्ट अप्स को हर तरह की मदद देगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने ई-कॉमर्स से जुड़ी तीन कंपनियों के साथ भागीदारी के अलावा देश में सॉफ्टवेयर प्रो 4 लैपटॉप को जनवरी में भारत में उतारने का एलान भी किया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने यहां कहा, 'कंप्यूटिंग ही भविष्य है और इसके लिए क्लाउडिंग और मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट में हम प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक बिजनेस और सरकारी संगठनों को ज्यादा कुशलता पूर्वक काम करने का मंच उपलब्ध कराना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और सरफेस प्रो 4 लोगों व सरकार के इन लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा।'

ई-कॉमर्स कंपनियों से भी किया करार : नडेला ने ई-कॉमर्स की तीन कंपनियों जस्ट डायल, पेटीएम और स्नैपडील के साथ भागीदारी की भी घोषणा की। तीनों ही कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों और क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल करेंगी। वर्ष 2020 तक देश में ई-कॉमर्स कारोबार 100 अरब डालर का हो जाएगा। फ्यूचर अनलीश्ड के नाम से माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में नडेला ने कहा छोटे बड़े सभी उद्यमी अपने कारोबार के विस्तार के लिए क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की स्मार्ट सिटी परिकल्पना को साकार करने में भी क्लाउडिंग अहम भूमिका निभाएगी। शहरों से जुड़ी समस्याओं के निदान तलाशने के लिए स्थानीय स्तर पर स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहित करने का निर्णय भी इसीलिए लिया गया है। इसके लिए जो स्टार्ट अप माइक्रोसॉफ्ट के अजूर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कंपनी 80 लाख रुपये तक की मदद उपलब्ध कराएगी। इस कार्यक्रम में आनंद महिंद्रा, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा और टाटा स्टारबक्स के सीईओ अवनी दवडा समेत भारतीय उद्योग जगत की कई हस्तियां मौजूद थीं।

जनवरी में आएगा सरफेस प्रो 4 : नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के दो फ्लैगशिप उत्पाद सरफेस प्रो 4 और माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 एक्सएल को भी भारत में लांच करने का एलान किया। सरफेस प्रो 4 हाइब्रिड लैपटॉप है। इसे लैपटॉप के साथ साथ टैबलेट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी इसे जनवरी में घरेलू बाजार में उतारेगी। सरफेस प्रो 4 इस सीरीज का पहला उत्पाद है, जो भारतीय बाजार में मिलेगा।

लूमिया एक्सएल अगले माह : इसके अलावा 5.7 इंच की स्क्रीन वाला स्मार्टफोन माइक्रोसॉफ्ट 950 एक्सएल भी दिसंबर से बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। लुमिया 950 भी मिलने लगेगा। दोनों ही विंडोज फोन हैं।

बिड़ला कॉर्प का मुनाफा घटा

कोलकाता : इस वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर को समात हुई तिमाही में एमपी बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीसीएल) के शुद्ध मुनाफे में 43 फीसद की गिरावट दर्ज की गयी है। आलोच्य अवधि में शुद्ध मुनाफा 18.48 करोड़ रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 32.46 करोड़ रुपए था। आलोच्य तिमाही में शुद्ध राजस्व 801.78 करोड़ रुपये रहा और इसमें 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 767.11 करोड़ रुपये था।

पोस्ता मंडी

कोलकाता बाजार भाव : दलहन (प्रतिक्विंटल) मूंग दाल : 9400-10700, मसूर दाल : 7400-10300, चना दाल : 6100-6800 मटर दाल : 5900-6550 दाल : 2850-3050, उड़द दाल : 11700-12800, मोठ दाल : 7700-8800, अरहर दाल : 14000-15500, अनाज (प्रति क्विंटल) चना : 5600-6500, मूंग : 7450-9300, मसूर : 6800-7300, अरहर : 9000-10400, मटर : 2600-3100, उड़द : 10500-11300, मोठ : 8000-8600, जौ : 1700-2000, ज्वार : 1800-2300, बाजरा : 1700-2000, मकई : 1200-1600, पापकार्न : 4500-4800, गेहूं उत्पाद (प्रति 90 किलो बैग) आटा : 2060-2090, मैदा : 2100-2130, सूजी : 2210-2240, मटर बेसन : 3130-3150, नमक (प्रति 50 किलोग्राम बोरी) 190-290, नमक (खुदरा)-140-180, चीनी (प्रति क्विंटल) बड़ी-30 मध्यम : 3000-3050 छोटी : 2860-2900, टीन गुड़ (प्रति क्विंटल) : 2550-2800, पैकेट गुड़ (लड्डू) :3100-3150, पैकेट गुड़ (चौका)-, बकेट गुड़ : 3000, : तिलहन एवं वनस्पति : मूंगफली तेल (प्रति 15 किलोग्राम टिन) : 1900, रिफाइंड मूंगफली तेल (प्रति 15 किलोग्राम टिन) :, सरसों तेल : (प्रति 15 किलो टिन) : 1500-1900, वनस्पति : 800-950, रिफाइंड सूर्यमुखी तेल (प्रति 15 किलो टिन) : 1200-1350, नारियल तेल : 14000, (प्रति क्विंटल), सरसों तेल : 11400-11600, रिफाइंड सोयाबिन तेल (प्रति क्विंटल) : 6425, रिफाइंड राइसब्रान तेल (प्रति क्विंटल) : 6600, रिफाइंड आयातित पामोलिन तेल (प्रति क्विंटल), रिफाइंड पामोलिन तेल, 5000, सरसों (पुराना) :, सरसों (नया), 5400, चावल (प्रति क्विंटल) कोर्स : 2000-2300, मिनीकट : 3000-3500, गोविंद भोग : 5400-5800, देहरादून : 5700-7700

मदर्स रेसिप ने एलमैक का किया अधिग्रहण

- चालू वित्त वर्ष में 30 फीसद बढ़ोतरी का लक्ष्य

जासं, कोलकाता : देसाई ब्रदर्स लिमिटेड के खाद्य विभाग मदर्स रेसिप ने अपने पोर्टफोलियो में नया अध्याय जोड़ते कोलकाता आधारित एलमैक एग्रो मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (ईएएमपीएल) का अधिग्रहण (घरेलू शाखा) किया है। पूर्वी क्षेत्र में अपने मौजूदा उत्पादों के विस्तार एवं उपस्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मदर्स रेसिप ने इस रणनीतिक समझौते की घोषणा की। इस अवसर पर गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एलमैक एग्रो मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनोद ठक्कर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस समझौते से मदर्स रेसिप ने चालू वित्त वर्ष में 30 फीसद बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। देसाई ब्रदर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक संजय देसाई ने कहा कि यह सौदा डीबीएल के खाद्य विभाग के लिए सकारात्मक विकास हो सकता है। एलमैक पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक मजबूत ब्रांड इक्विटी है जो हमें अपने मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करने और उत्पाद श्रेणियों के विस्तार में मदद करेगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में कम से कम 25 फीसद की अतिरिक्त वृद्धि होगी। इस ब्रांड के तहत अगले तीन वर्षों में 70 करोड़ रुपए से अधिक के बिक्री कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान में ऑर्गेनिक रिसोर्ट बनायेगा मणि ग्रुप

कोलकाता : रियल इस्टेट व अतिथि सत्कार क्षेत्र में अग्रणी कोलकाता स्थित मणि ग्रुप, राजस्थान के नागौर जिले के अजमेर के निकट इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव स्टार रेटेड ऑर्गेनिक रिसोर्ट तैयार करेगा। इस संबंध में मणि ग्रुप ने गुरुवार को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर मणि ग्रुप के सीइओ संजय झुनझुनवाला ने बताया कि परियोजना का आनुमानिक खर्च 110 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित स्टार रेटेड ऑर्गेनिक रिसोर्ट लगभग 300 बीघे की जमीन पर तैयार किया जायेगा। इस परियोजना से 450 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ऑर्गेनिक रिसोर्ट को मणि ग्रुप की कंपनी, ओपुलेंट रिसोर्ट्स प्रा लि. द्वारा विकसित किया जायेगा।

उदय से सुधरेगी बिजली क्षेत्र की दशा

कैबिनेट का फैसला

- बिजली क्षेत्र में सुधार के सबसे बड़े एजेंडे को दी मंजूरी
- कर्ज के आधे हिस्से के बराबर बांड जारी करेंगी राज्य सरकारें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भयंकर कर्ज में डूबी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को कर्ज से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना लागू कर दी है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नाम की इस योजना को गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बकाया बैंकिंग कर्ज के बड़े हिस्से का बोझ राज्य सरकारें उठाएंगी। इसके बदले राज्यों की तरफ से बांड जारी किए जाएंगे। पैकेज यह भी सुनिश्चित करेगा कि हर घर में स्मार्ट मीटर लगे और बिजली की पूरी कीमत ग्राहकों से वसूली जाए।

बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राज्यों की डिस्कॉम पर बैंकों का लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह कर्ज ही बिजली क्षेत्र की मौजूदा सारी समस्याओं की जड़ में है। ज्यादा कर्ज होने की वजह से ये कंपनियां नई बिजली नहीं खरीद रही हैं। इससे ग्राहकों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिक्री नहीं होने की वजह से पावर प्लांट ने बिजली उत्पादन घटा दिया है। पहले के कर्ज फंस जाने की वजह से बैंक बिजली कंपनियों को नया लोन नहीं दे रहे हैं। अगले पांच वर्षों में हर घर को 24 घंटे बिजली देने की सरकारी योजना पर भी सवाल उठ रहे थे। उदय के जरिये बिजली वितरण कंपनियां वर्ष 2018-19 तक कर्ज मुक्त हो सकेंगी।

डिस्कॉम के उद्धार की राह : उदय के तहत निकाले गए फॉर्मूले के मुताबिक डिस्कॉम की कार्यकुशलता बढ़ाई जाएगी।साथ ही, बिजली की लागत भी कम की जाएगी। डिस्कॉम पर ब्याज की लागत को भी घटाया जाएगा। हर राज्य में ये कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज करेंगी। पहले चरण में 500 यूनिट हर महीने बिजली खपत करने वाले ग्राहकों के यहां स्मार्ट मीटर लगेंगे। उसके बाद 200 यूनिट वाले ग्राहकों के यहां भी इसे लगाया जाएगा। इससे बिजली की चोरी काफी हद तक कम हो जाएगी।

बिजली दरें तिमाही बढ़ाने का विकल्प : योजना की निगरानी के लिए हर महीने की 10 तारीख को बिजली मंत्रालय के अफसर राज्यों के साथ बैठक करेंगे। सुनिश्चित किया जाएगा कि हर राज्य में बिजली की पूरी लागत ग्राहकों से वसूल की जाए।